

प्रेषक,

डा० आर० राजेश कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनांक: २६ मई, 2016

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक:-775/रिबेट शासनादेश पत्रा०/उ०खा०ग्रा०बो०/2015-16 दिनांक 31.08.2015, पत्रांक:-1775/एम०डी०ए० पत्रावली/उ०खा०ग्रा०बो०/2015-16 दिनांक 18.02.2016 तथा पत्रांक:-1975/एम०डी०ए० पत्रावली/उ०खा०ग्रा०बो०/2015-16 दिनांक 17.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.04.2010 से खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर "विपणन विकास सहायता (एम०डी०ए०) योजना" लागू की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्य कर रहे कतिन/बुनकरों को सीधा लाभ प्रदान कराये जाने एवं आयोग तथा बोर्ड के मध्य संस्थाओं को भुगतान करने में सहूलियत के उद्देश्य से उक्त योजना के तर्ज पर ही वित्तीय वर्ष 2016-17 से उत्तराखण्ड राज्य में भी "खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना" के स्थान पर "विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना" निम्नवत लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना:-

1 पृष्ठ भूमि:-

(i) 'खादी' हाथकता एवं हाथबुना कपड़ा है जो कि लगभग दस लाख परंपरागत ग्रामीण कारीगरों के द्वारा तैयार किया जाता है। हाथकता एवं हाथबुना होने का गुण खादी का विशिष्ट बिक्रय गुण/कारक है। राज्य सरकार विगत वर्षों में खादी की फुटकर बिक्री मूल्य पर रिबेट के रूप में जानी जाने वाली बिक्री प्रोत्साहन सहायता प्रदान करती आ रही है ताकि बाजार में दूसरे वस्त्र उत्पादों से बराबरी करने में उत्पाद को सहूलियत हो सके।

(ii) विगत वर्षों में लागू रही रिबेट योजना खादी तथा पौली वस्त्र फुटकर अंश पर छूट प्रदान करती है। रिबेट योजना के अंतर्गत खादी के उत्पादों में 108 दिनों के लिये लोकल त्योहारों से सामंजस्य करते हुए एक वर्ष में 10 प्रतिशत की दर से रिबेट दिये जाने का प्राविधान रहा है।

(iii) खादी की बिक्री बढ़ाने में इसकी प्रभावकारिता के आँकड़ों के लिये रिबेट योजना का अध्ययन कतिपय समितियों द्वारा किया जा चुका है। इन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनेक मार्गदर्शक योजनाओं के साथ प्रयोग करने के बाद रिबेट के स्थान पर उत्पादन के ऊपर बाजार विकास सहायता स्कीम को प्रारम्भ करते हुए राज्य सरकार से भी योजना अपनाने की संस्तुति की गई है। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी होगी। योजना द्वारा कारीगरों के उपार्जन में बढोत्तरी पर पर्याप्त जोर देने के साथ-साथ ग्राहकों हेतु उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करके खादी क्षेत्र के क्रियाकलापों में नयापन लाया जा सकेगा।

2 एम.डी.ए. योजना की प्रमुख विशेषतायें:-

(i) कॉस्ट चार्ट केवल कच्ची खादी उत्पादन के वेट प्रोसेसिंग तक की मूल्य दशा तक की गणना करने के प्रयोजन हेतु जारी रहेगा जो एम.डी.ए की गणना का आधार बनेगा। इस प्रकार से एम.डी.ए. स्कीम में कॉस्ट चार्ट से विक्रय मूल्य का नियंत्रण हटेगा एवं सम्बन्धता नहीं रहेगी तथा संस्थाओं को खादी का मूल्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा ताकि उत्पाद को बाजार द्वारा नियत मूल्य पर बेचा जा सके। संक्षेप में यह योजना खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिये गतिशील मूल्यन(प्राइसिंग) की गुंजाइश प्रदान करेगी।

(ii) उत्पादन पर एम.डी.ए. स्कीम का उद्देश्य वर्तमान रिबेट स्कीम के विपरीत जिसमें कि अधिकतम बिक्री 108 दिनों के स्पेशल रिबेट सीजन के दौरान होती है, को समान रूप से पूरे वर्ष भर बाँटना है।

(iii) वर्षपर्यन्त योजना के लाभ सहित बिक्री से खादी संस्थाओं को अपनी सम्पत्ति सूची का स्तर नीचे रखने में सहायता मिलेगी। इससे कार्यशील पूँजी की गतिशीलता का अधिक अवसर मिलेगा।

(iv) एम.डी.ए. सहायता का एक नियत भाग स्पेशल प्रोत्साहन/बोनस के रूप में सीधे आर्टिजन को जायेगा और उनकी आजीविका में बढोत्तरी होगी।

(v) एम.डी.ए. स्कीम के अधीन उत्पादन हेतु संस्थावार लक्ष्य उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गठित समिति की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से तय तथा स्वीकृत किया जायेगा।

(vi) संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के विरुद्ध एम.डी.ए. सहायता त्रैमासिक आधार पर अवमुक्त किया जायेगा।

(vii) एम.डी.ए. का झुकाव मात्र उच्च खादी मूल्य भाग की ओर नहीं होगा और खादी संस्थायें बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करने हेतु बाध्य होंगी। प्रोत्साहन का उपभोग करने वाली संस्था एक ही समय में एम.डी.ए. के लिये पात्र नहीं होगी।

3 एम.डी.ए की परिभाषा:- उत्पादन पर एम.डी.ए. एक सहायता है, जिसे प्रमाणित खादी संस्थाओं द्वारा खादी एवं पौलीवस्त्र के उत्पादन की लागत पर दिया जाना प्रस्तावित है। केवल वे खादी संस्थायें जिनके पास वैध प्रमाणपत्र है तथा ए+, ए, बी. तथा सी में श्रेणीकृत है, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से एम.डी.ए. अनुदान उपभोग के लिये पात्र हैं।

4 एम.डी.ए. की दर (रेट):-

खादी (सूती, रेशमी, ऊनी तथा पौलीवस्त्र) के उत्पादन लागत पर 10 प्रतिशत की दर से एम.डी.ए. सहायता उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गठित समिति द्वारा मंजूर उत्पादन लक्ष्य की सीमा तक स्वीकृत किया जायेगा।

5 उत्पादन की परिभाषा:-

(i) खादी उत्पादन क्रिया कताई, बुनाई तथा खादी की वेट प्रोसेसिंग की एक मिश्रित क्रिया है जिसमें कच्चे माल की लागत, पंजीकृत कतकरों द्वारा हाथ कताई तथा पंजीकृत बुनकरों द्वारा हथकरघे पर बुनाई के साथ ही कतकरों/रीलरों तथा बुनकरों की मजदूरी/रूपान्तरण(कनवर्जन) चार्ज एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा के उपायों का प्रावधान, वेट प्रोसेसिंग (ब्लीचिंग, डाईंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग) आदि सम्मिलित किये गये हैं। खादी वस्त्र का पहनने को तैयार तथा उपयोग के लिये तैयार आइटमों में परिवर्तन उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं होगा।

(ii) उत्पादन की लागत:-

एम.डी.ए. के प्रयोजन हेतु खादी एवं पौलीवस्त्र के संदर्भ में उत्पादन लागत में निम्नलिखित शामिल हैं :-

$$\begin{aligned}
 & \text{कच्चे माल की लागत} \\
 & + \\
 & \text{प्रोसेस वेस्टेज, आर्टिजन प्रोत्साहन तथा आर्टिजन कल्याण कोष आदि सहित कताई/रीलिंग तथा} \\
 & \text{बुनाई चार्ज} \\
 & + \\
 & \text{वेट प्रोसेसिंग तथा ब्लीचिंग, डाईंग, मर्सराइजिंग, फिनिशिंग तथा प्रिंटिंग चार्ज आदि के साथ-साथ} \\
 & \text{प्रोसेस वेस्टेज} \\
 & +
 \end{aligned}$$

अनुमन्य मार्जिन (स्थापना खर्च का पूरा करने के हेतु)

नोट :-

- वस्त्र के रेडिमेड, एम्बाइडरी आदि में परिवर्तन हेतु मूल्य सम्वर्धन चार्ज को उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि बाजारी शक्तियाँ मूल्य सम्वर्धित उत्पादों के मूल्य निर्धारित करेगी।
- एम.डी.ए. के प्रयोजनार्थ केवीआईसी एवं केवीआईबी के द्वारा चलायी जा रही इकाइयों सहित बिक्रीकर्ता संस्था अथवा बिक्री भण्डार का आशय होगा दूसरी संस्थाओं से खरीदी गयी खादी की बिक्री में संलग्न संस्था।

- मिली-जुली संस्था से आशय वह संस्था है जो उत्पादन तथा बिक्री के कार्य में संलग्न हो। मिली जुली संस्था विशिष्ट उत्पादन कर रही संस्था से खादी खरीद सकती है तथा वे भी विक्रय संस्था को खादी बेच सकते हैं।
- खादी के संदर्भ में उत्पादन पर आधारित एम.डी.ए. की गणना हेतु फॉर्मूला पौलवस्त्र के लिये भी प्रयोज्य होगा।
- अनुमन्य प्रावधान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गाइडलान्स में क्रमशः ट्रेड खर्च, बैंक ब्याज, बीमा हेतु प्राइम कॉस्ट पर 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत की दर से नियत किया गया है।
- स्वीकार्य मार्जिन का आशय केवीआईसी की केन्द्रीय प्रमाणपत्र समिति द्वारा स्थापना खर्च को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय मार्जिन, वर्तमान गाइडलाइन्स के अनुसार खादी के लिए अनुज्ञेय स्थापना मार्जिन प्राइम कॉस्ट पर 20 प्रतिशत है। वहीं मसलिन ऊन व रेशम के लिए 25 प्रतिशत है। पौलीवस्त्र के लिए स्वीकार्य मार्जिन भी प्राइम कॉस्ट का 25 प्रतिशत है।

प्राइम कॉस्ट का आशय कच्चे सामान की कॉस्ट

+

ग्रे क्लार्थ तक कनवर्जन(परिवर्तन) चार्ज

+

प्रोसेसिंग चार्ज परन्तु ट्रेड खर्च (3 प्रतिशत), बैंक ब्याज (4 प्रतिशत), बीमा (1 प्रतिशत) का प्रावधान तथा केवीआईसी लागत स्ट्रक्चर में दिये गये स्थापना खर्च शामिल नहीं है।

6 एम.डी.ए. अनुदान की उपयोगिता के लिये पद्धति और उद्देश्य : -

- (i) उत्पादन पर एम.डी.ए. योजना खादी संस्थाओं को जाँच करने योग्य तथा वास्तविक स्थिति की ओर फन्ड्स की आवश्यकता पर आधारित उपयोग करने तथा आर्टिजन की आजीविका में सुधार करने के लिये कार्य तथा खादी एवं पौली वस्त्र के सुधार के लिये भी अनुमति प्रदान करती है।
- (ii) उत्पादन पर एम.डी.ए. की संपूर्ण राशि उत्पादन संस्था द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के दावों की और स्टॉक होल्डर्स यथा कतिनों एवं बुनकरों, उत्पादक संस्थाओं तथा बिक्री करने वाली संस्थाओं में क्रमशः 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत के अनुपात में आवंटित की जायेगी।
- (iii) कुल एम.डी.ए. राशि का 25 प्रतिशत कतिनों एवं बुनकरों को प्रोत्साहन अथवा बोनस के रूप में उनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खातों को कॉस्ट चार्ट में नियत किये गये की भाँति, उनके सामान्य उपार्जन के अतिरिक्त पारित की जायेगी। एम.डी.ए. ग्रांट से प्राप्त इस प्रकार के अतिरिक्त पारिश्रमिक को खादी की लागत में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त 25 प्रतिशत एम.डी.ए. राशि का उपयोग उन कामगारों को जो संस्था के कर्मचारी हैं तथा उत्पादन कार्य एवं बिक्री/मार्केटिंग/अकाउन्ट्स आदि के निरीक्षण कार्य में संलग्न हैं, के लिये नहीं किया जा सकता है।

26/5 0
(v) कुल एम.डी.ए राशि का 30 प्रतिशत खादी उत्पादक संस्थाओं द्वारा उपकरणों/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण में उपयोग किया जायेगा।

(vi) उत्पादनकर्ता संस्था कुल एम.डी.ए. का 45 प्रतिशत जो स्कीम के अनुसार बिक्रीकर्ता संस्थाओं के लिए अलग से रखा गया है, बिक्रीकर्ता संस्था को थोक बिक्री के समय ट्रान्सफर करेगी। ट्रान्सफर बीजक के द्वारा किया जाना चाहिए। विक्रयकर्ता संस्था द्वारा इस एम.डी.ए. राशि का उपयोग नवीकरण/बिक्री भण्डारों में सुधार करने, विक्रेताओं के प्रशिक्षण, कम्प्यूटराइजेशन, डिजाइनों के विकास, प्रचार, छूट(यदि जरूरत पड़े) में किया जायेगा। थोक में खादी बेचने वाली खादी संस्थायें उपर्युक्त (कुल एम.डी.ए. का 45 प्रतिशत) को खरीददार संस्था को हस्तांतरित करेगी।

(vii) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गठित समिति के द्वारा मंजूर थोक बिक्री लक्ष्य के विरुद्ध किये जाने वाले डी.जी., एस. एवं डी. दर संविदा (आर.सी.) के अधीन सरकारी आपूर्ति के प्रयोजन हेतु खादी एवं पौलीवस्त्र उत्पाद का उत्पादन एम.डी.ए. के लिए पूर्णतया पात्र नहीं है क्योंकि ये वस्तुयें फुटकर बिक्री भण्डारों द्वारा नहीं बेचे जाते हैं। अतएव इस प्रकार की वस्तुयें फुटकर बिक्री कार्यों के लिए अलग से रखे गये, एम.डी.ए. पोषण के लिये योग्य नहीं हैं। इसलिए आर.सी. वस्तुयें जैसा कि सामान्य खादी के लिए उपयुक्त है, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से 10 प्रतिशत के स्थान पर 5.5 प्रतिशत एम.डी.ए. के लिये पात्र होंगी।

(viii) इस फारमूले में जरूरत पड़ने पर वास्तविक कार्य संपादन का अनुश्रवण होने तथा योजना में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उक्त कमियाँ दूर करने हेतु बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

7 कारीगरों की बढ़ी हुई मजदूरी हेतु उपाय/सुरक्षा : -

कारीगरों के उच्च उपार्जित धन को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा—

(i) फण्ड्स के विशिष्ट प्रयोजनों के उपयोग हेतु वचनबद्धता लेते समय संस्था द्वारा इस आशय का कि संस्था कपड़े की गुणवत्ता एवं डिजाइन के साथ समझौता किये बगैर कारीगरों की मजदूरी बढ़ाने के उपाय करेगी; जिसका स्पष्ट संकेत संस्था द्वारा एम.डी.ए. क्लेम फारमेट में किया जायेगा।

(ii) संस्था को नियमित अन्तराल पर अधिमानः पाक्षिक रूप से तथा माह से अधिक देर से नहीं, बैंक एकाउण्ट या पोस्ट ऑफिस खाते के माध्यम से कारीगरों को भुगतान करना होगा तथा प्रत्येक कारीगर को किये गये भुगतान का रिकार्ड सत्यापन करने हेतु रखना होगा।

(iii) संस्था राज्य स्तरीय आर्टिजन वेलफेयर फण्ड को राज्य स्तरीय ट्रस्टों को धन भेजेगी एवं फण्ड के प्रेषण की रसीद को क्लेम फारमेट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(iv) संस्थाओं को सभी कारीगरों को केवीआईसी द्वारा प्रारम्भ की गयी खादी कारीगर जन श्री बीमा योजना तथा इस प्रकार की अन्य वेलफेयर योजनायें जो उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार की स्वीकृत से प्रारम्भ की जाती हों; की परिधि के अन्तर्गत लाना होगा।

(v) एम.डी.ए. की त्रैमासिक अवमुक्ति के लिये दावा प्रस्तुत करते समय उत्पादक संस्था इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगी कि पूर्व तिमाही के लिये कृतिनों तथा बुनकरों एवं विक्रय संस्थाओं

का एम.डी.ए. भाग क्रमशः 25 प्रतिशत व 45 प्रतिशत के अनुपात में उनकी संतुष्टि के निमित्त अवमुक्त किया जा चुका है। अगली तिमाही के लिये एम.डी.ए. भुगतान अवमुक्त करते समय इस सम्बन्ध में कोई चूक होने पर खादी बोर्ड इस पर विचार करेगा।

(vi) प्रत्येक संस्था के एम.डी.ए. क्लेम का निपटान करते समय उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का अनुपात सुनिश्चित करेगा।

(vii) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एम.डी.ए. क्लेम्स के कम से कम 10 प्रतिशत का रैन्डम चैक करेगी जिसमें सभी लेन-देनों का भौतिक सत्यापन तथा खास विचारणीय रूप से कारीगरों को जारी की गयी पास बुक तथा कारीगरों को किये गये भुगतान तथा क्षमता वर्धन पर किया गया खर्च आदि शामिल होगा

8 एम.डी.ए. क्लेम की अवधि: -

(i) उत्पादक संस्थाएँ वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन के आधार पर त्रैमासिक एम.डी.ए. दावा प्रस्तुत करेंगी। यदि कोई अन्तर हो, तो उसे वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में, चार्टर्ड अकाउन्टैंट द्वारा ऑडिट अकाउन्ट्स के आधार पर ऐडजस्ट किया जायेगा। एम. डी.ए. की धनराशि उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ii) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एम.डी.ए. दावों के निपटान में भुगतान की वास्तविक अवमुक्ति शामिल होगी, जहाँ कहीं सम्भव होगा छः माह के अन्दर आर०टी०जी०एस० द्वारा भुगतान प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।

(iii) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जनपदीय कार्यालयों की जिम्मेदारी होगी की वे समय पर एम.डी.ए. दावों का निपटान सुनिश्चित करें एवं प्राप्त दावों, निस्तारण किये गये दावों तथा पूर्व तिमाही के दौरान नियत समय के अन्दर दावों का निस्तारण ना होने के कारण दर्शाते हुए त्रैमासिक रिपोर्ट उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को माह सितम्बर, माह दिसम्बर, माह मार्च एवं माह जून के प्रथम दिवस को प्रस्तुत करेंगे।

9 अन्तिम शेष स्टाक:-

(i) अन्तिम शेष स्टाक निम्न प्रकार से निकाला जायेगा।

(ii) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अगले वर्ष के लिए उत्पादन, फुटकर बिक्री तथा थोक बिक्री के लक्ष्यों की संस्तुति करते समय कड़ाई से मापदण्ड का पालन करेंगे जिससे कि पूर्व वर्ष के दौरान अन्तिम शेष स्टाक के ढेर लगने से बचा जा सके।

(iii) संस्थाएँ वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को अन्तिम शेष स्टाक की स्थिति जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को वार्षिक स्टाक टेकिंग स्टेटमेंट (केन्द्रवार) जो संस्था के स्टाक लेने वाले व्यक्ति द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें संस्था के प्राधिकृत पदधारियों के हस्ताक्षर हो, प्रस्तुत करेगी।

258
(iv) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आडिट एवं टैक्नीकल मानिट्रिंग (अनुश्रवण), निरीक्षण करते समय रैंडम टेस्ट चेक कर इस पहलू पर चेक/मानिट्रिंग सुनिश्चित करेंगे।

(v) अन्तिम शेष स्टॉक पोजीशन की सत्यता का प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा यथाविधि प्रमाणित ऑडिटेड वैलेंस शीट से किया जायेगा।

(vi) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संस्थाओं ने वार्षिक स्टॉक स्टेटमेंट अपने-अपने कार्यालयों को समय पर प्रस्तुत कर दिया है तथा इसे बजट चर्चा के रिकार्ड नोट में भी कर लिया जायेगा।

10 एम.डी.ए. उपयोग की अवधि : -

निश्चित प्रयोजनों जैसे कि आधुनिकीकरण, नवीकरण शोध एवं विकास आदि हेतु एम.डी.ए. के उपयोग में एक वर्ष से अधिक की अवधि लगेगी। ऐसे मामलों में खादी संस्थाओं को वास्तविक प्राप्ति की तिथि से उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गठित समिति की विशेष स्वीकृति से दो वर्षों तक एम.डी.ए. खर्च करने की आज्ञा दी जायेगी। एम.डी.ए. राशि के प्रभावकारी ढंग से व्यवस्था करने के उद्देश्य से संस्थाओं की तरफ से यह बाध्यकारी होगा कि एक पृथक बैंक अकाउन्ट रखा जाये जो कि उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

11 एम.डी.ए. क्लेम हेतु डॉक्यूमेंटेशन : -

एम.डी.ए. पात्र संस्थाओं को नियम फारमेट (अनुलग्नक -1,2,3,4 एवं 5) के अनुसार विस्तृत क्लेम्स के प्रस्तुतिकरण पर वितरित किया जायेगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा गठित समिति को एम.डी.ए. क्लेम के सेटलमेंट का त्रैमासिक ब्यौरा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर तथा वर्ष के अन्त में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए एक समेकित स्टेटमेंट भेजेंगे।

12 सदुपयोगिता प्रमाण पत्र का भेजा जाना : -

(i) एम.डी.ए. का उपभोग करने वाली खादी संस्थायें रजि. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सी.ए) द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र सी.ए. का रजिस्ट्रेशन नं० तथा पता दर्शाते हुए वार्षिक रूप से भेजने के लिए बाध्य होंगी। उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र का फारमेट, गाइडलाइन्स आदि प्रचारित (सर्कुलेट) की जायेंगी। उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार को धनराशि उपयोगिता का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ii) एम.डी.ए. का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजते समय सी.ए. से संस्था की वित्तीय योग्यता, नियमों, विनियमों का परिपालन उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से जारी की गई गाइडलाइन्स, वित्तीय स्वीकृतियाँ, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गठित समिति की संस्तुतियों आदि पर अपनी रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा की जाती है तथा अवस्थापना सुविधाओं यथा चर्खे, करघे, आर्टिजनों, कच्चे माल की उपलब्धता, सहमत क्षेत्रों में एम.डी.ए. उपयोग का उचित प्रयोग आदि के अस्तित्व से अपने आप को संतुष्ट करें एवं इन बिन्दुओं पर संतुष्ट होने के बाद की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की सत्यता प्रमाणित मानी जायेगी।

3656

(iii) सम्बन्धित सी.ए. यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को सीधे उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पते पर जारी करेंगे ताकि जबाबदेही एवं विशुद्धता का पता लगाया जा सके।

13 उत्पादन पर एम.डी.ए. का टेस्ट ऑडिट एवं मॉनिटरिंग/टेस्ट चेक :-

(i) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एम.डी.ए. का उपभोग करने वाली सभी संस्थाओं के सम्बन्ध में अपनी ऑडिट टीमों के द्वारा एम.डी.ए. क्लेमों का चेक/टेस्ट ऑडिट करवायेगा। उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड टेस्ट/चेक करने के लिये अपना अधिकार सुरक्षित रखेगा और किसी भी दुरुपयोग होने की दशा में यह खादी संस्थाओं के एकाउन्ट्स का पूरा ऑडिट करने का आदेश कर सकता है। एम.डी.ए. क्लेम्स एम.एस.एम.ई. विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए खुला रहेगा।

(ii) चूँकि एम.डी.ए. के लिए फन्ड्स सार्वजनिक फन्ड्स से प्रदान किए जाते हैं इसलिए राज्य सरकार की आडिट टीम तथा भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परिक्षक को ऑडिट/टेस्ट चेक अथवा जैसा भी वह निर्णय लें, करने का अधिकार होगा।

14 एम.डी.ए. के ट्रांसफर में विवाद का निपटारा :-

(i) उत्पादक संस्थाओं द्वारा एम.डी.ए. के दूसरे स्टॉक धारक को खासकर विक्रयकर्ता संस्था को अहस्तांतरण या असंगत हस्तांतरण किये जाने के मामले में स्टॉक धारक को ऐसे लेने देन को तुरन्त ही (लेन देन के एक माह के अन्दर) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नोटिस में लाना चाहिये जो उत्पादक संस्थाओं को एम.डी.ए. का इच्छित भाग ट्रांसफर करने का निर्देश देंगे। खादी उत्पादक संस्थाओं के निर्देशों के न मानने के मामले में वह (उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) खादी उत्पादनकर्ता संस्थाओं के दावों से उक्त धनराशि काटेंगे और बिक्रीकर्ता संस्थाओं सहित स्टॉक धारक को भेजेंगे।

(ii) प्रथम लेनदेन के लिये कोई जुर्माना नहीं लगाया जायेगा तथा उसके बाद के लेनदेन हेतु उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लेनदेन की तिथि से 5 प्रतिशत ब्याज का हिसाब लगाने के साथ इच्छित एम.डी.ए. धनराशि की वसूली की व्यवस्था करेंगे तथा आर्टिजनों और बुनकरों एवं विक्रय संस्था को भेजेंगे।

(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सभी विवादों के लिये अपीलीय प्राधिकारी होंगे तथा सभी खादी संस्थाओं को उनका निर्णय मान्य होगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 संख्या:-50/XXVII(2) /2016 दिनांक 12 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० आर० राजेश कुमार)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: ११४ (१)/VII-2-16/111-एम०एस०एम०ई०/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुँमरु/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी समन्वय निदेशालय, 3-इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-56
7. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
9. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
10. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. निजी सचिव—मा० मंत्री, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड—फाईल।

आज्ञा से,

Dhirendra

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)

अनु सचिव।